जयपुर • कोटा • बीकानेर • उदयपुर • अजमेर • जालोर • हिण्डौनसिटी • चूरू

राष्ट्रदूत

epaper.rashtradoot.com

कोटा

Rashtradoot

फोनः- 2386031, 2386032 फैक्सः- 0744-2386033 वर्षः 47 संख्याः 265 प्रभात कोटा, शुक्रवार 8 जुलाई, 2022 कोटा/24/2012-14 पृष्ठ 8 मूल्य 1.20 रु.

दक्षिण पश्चिम चीन में पुरातत्वविदों को 3000 साल पुरानी 13000 वस्तुएं मिली हैं, जिनमें कछुए के आवरण के आकार का बक्सा और एक बलिवेदी भी है। अधिकांश वस्तुएं स्वर्ण, कांस्य ओर जेड से बनी हैं। सभी वस्तुएं सैनसिनहुई पुरास्थल के पास बलि देने वाले गड्ढों से मिली हैं। इतिहासकार सैनसिनहुई संस्कृति के बारे में तुलनात्मक रूप से बहुत कम जानते हैं क्योंकि इसके ना तो कोई लिखित रिकॉर्ड हैं ना ही वंशज, हालांकि अधिकांश का मत है कि यह संस्कृति प्राचीन शू साम्राज्य का हिस्सा थी। उम्मीद की जा रही है कि नई खोज से इस साम्राज्य के बारे में कुछ जानकारी मिलेगी, जिसने पश्चिमी सिचुआन बेसिन पर राज किया था। यह क्षेत्र यांक्ट्सी नदी की ऊपरी धारा के समीप है। सन् 316 ईसा पूर्व में स्टेट ऑफ चिन ने इस पर कब्जा कर लिया था। सिचुआन प्रॉविंशिअल कल्चरल रैलिक्स और आर्किओलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, पीकिंग युनिवर्सिटी, शिचुआन युनिवर्सिटी और अन्य रिसर्च संस्थानों के पुरातत्वविदों की एक संयुक्त टीम 2020 से ही यहाँ पर 6 गड्ढों की जांच कर रही है। नवीनतम उत्खनन में पुरातत्व विशेषज्ञों को 3,155 ऐसी वस्तुएं मिली हैं जो किसी हद तक मूल स्वरुप में हैं। इनमें 2000 कांसे के बर्तन और मूर्तियां हैं। एक गड्ढे में 3 फीट ऊंची वेदी भी मिली है। माना जाता है कि शू सभ्यता के लोग वेदी पर स्वर्ग, पृथ्वी तथा अपने पूर्वजों को भोग प्रसाद अर्पित करते थे। गड्ढों के पास से बांस, सोयाबीन, सरकंडे, मवेशी, जंगली सुअर आदि के अवशेष मिले हैं, संभवतया यह समस्त सामग्री पूजा में अर्पित की जाती थी। सैनसिनहुई कल्चरल रैलिक्स एवं आर्किऑलजी रिसर्च इंस्टीट्यूट के निदेशक रान होंगलिन ने बताया कि इस स्थान पर मिली विविध प्रकार की सामग्री चीन की प्राचीन सभ्यताओं में सांस्कृतिक आदान- प्रदान दर्शाती हैं। उन्होंने कहा, इंसान के सिर और सांप के शरीर वाली मूर्तियां प्राचीन शू सभ्यता की विशेषता हैं। यहां पर मिले पूजा के काम आने वाले बर्तन, जिन्हें ''ज़ुन'' कहा जाता है, चुंगयुऐन क्षेत्र की सांस्कृतिक विशेषता हैं। सबसे पहले 1920 में अनायास ही एक किसान को 4.6 वर्ग मील के इस क्षेत्र में एक वस्तु मिली थी तब से लेकर अब तक यहां हजारों वस्तुएं मिल चुकी हैं। गत वर्ष भी कुछ कलाकृतियां मिली थीं, जिसमें 100 ग्राम वजन का गोल्डन मास्क, हाथी दांत के स्मृति चिन्ह व जेड से बना चाकू शामिल है।

बोरिस जॉनसन ने इस्तीफा देने का निर्णय लिया

भारतीय मूल के ऋषि सुनक प्र.मंत्री की दौड़ में

-डॉ. सतीश मिश्रा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। भारतीय मूल के व्यक्ति ऋषि सुनक इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने के शीर्ष दावेदारों में शामिल है। ज्ञातव्य है कि पिछले दो दिनों उनकी सरकार से दिये जाने वाले इस्तीफों की बाढ़ के फलस्वरूप, वर्तमान प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने अपने पद से इस्तीफा देने का निर्णय ले लिया है।

सुनक, जिनक राजकोष के चांसलर पद से इस्तीफा देने से प्रेरित होकर, बोरिस जॉनसन के खिलाफ इस्तीफों की बौछार होने लगी थीं, इंग्लैंड के अगले प्रधानमंत्री बनने की दौड़ में शामिल माने जा रहे हैं। अगर वे प्रधानमंत्री बन जाते हैं, तो वे ब्रिटिश प्रधानमंत्री बनने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति होंगे।

- **सुनक के दादा पंजाब से आकर ब्रिटेन में बसे थे। चालीस वर्षीय सुनक इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति के दामाद हैं। कैलिफोर्निया में अध्ययन करते समय, वे नारायण मूर्ति की पुत्री अक्षता, जो भी कैलिफोर्निया में पढ़ रही थी, से मिले थे तथा अब दो पुत्रियों के पिता हैं।**
- **सुनक को बोरिस जॉनसन ने, फरवरी 2020 में अपनी कैबिनेट में वित्तमंत्री बनाया था।**
- **पर अब सुनक के कैबिनेट से इस्तीफे के बाद, बोरिस के मंत्रिमण्डल में भगदड़ सी मच गई तथा अन्ततोगत्वा दबाव इतना बना कि, बोरिस जॉनसन ने त्याग पत्र देने का निर्णय लिया।**
- **बोरिस जॉनसन ने 2019 के आम चुनाव में अपनी पार्टी, कंज़र्वेटिव पार्टी को, भारी बहुमत से विजयी बनाया था, पर, अब उनका इस्तीफा देना काफी निराशाजनक बात है, उनके लिये।**
- **कल तक बोरिस जॉनसन अडिग थे कि, वे अपने पद से इस्तीफा नहीं देंगे, उनका विश्वास था कि, वे किसी से दबने वाले नहीं, मजबूत नेता हैं। यूक्रेन के आक्रमण के बाद उन्होंने काफी सशक्त व निर्णायक भूमिका निभाई थी, यूरोप व अन्य पश्चिमी देशों को रूस के खिलाफ बांधकर रखने में।**

उनके प्रशासन पर घोटालों के अनेकानेक आरोपों के बावजूद, जॉनसन अपने पद से नहीं हटने पर अड़े रहे थे, लेकिन वे उस समय विधि-विधान के आगे झुक गये, जब उनकी सरकार से परेशान दर्जनों मंत्रियों, उपमंत्रियों तथा उनके कैबिनेट के सदस्यों, जिनमें नवनियुक्त चांसलर ऑफ एक्सचैकर नदीम ज़हावी भी शामिल थे, ने उनके मुँह पर उनसे कहा कि उन्हें पद छोड़ देना चाहिये।

कल तक, ब्रिटिश प्रधानमंत्री अपनी टीम सहित अपने हठ पर अड़े हुये थे तथा कह रहे थे कि उनका इरादा रिक्त हुये पदों को भरना हैं लेकिन इस्तीफों के सिलसिले में आज सुबह दो कैबिनेट मंत्रियों के इस्तीफे और शामिल हो गये तथा इनके साथ ही कुछ उपमंत्रियों के इस्तीफे भी आ गये। जहावी ने ट्वीट किया कि यह स्थिति ''चलती रहने वाली नहीं'' है तथा इस सबसे बाध्य होकर, जॉनसन अपने बचाव की कोशिशें बंद कर दीं।

एक ऐसे प्रधानमंत्री, जिसने 2019

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

हाई कोर्ट ने रीट भर्ती-2021 पेपर लीक की जांच सी.बी.आई. को सौंपने से इंकार किया

अदालत का मत था कि, स्पैशल ऑपरेशन ग्रुप (एस.ओ.जी.) सुचारू रूप से जांच कर रहा है और जांच के खिलाफ शिकायत साबित नहीं हुई है

-यादवेन्द्र शर्मा-

जयपुर, 7 जुलाई। रीट भर्ती 2021 लैवल 2 परीक्षा मामले में अदालत ने एस.ओ.जी. के ए.डी.जी. अशोक राठौड़ से सुनवाई के दौरान पूछा कि क्या अभी तक की जांच से वह संतुष्ट हैं, तो उन्होंने कहा कि एस.ओ.जी. ने अभी तक इस मामले में पेपर लीक करने वाले मुख्य आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। उन्होंने अदालत को कहा कि, एस.ओ.जी. ने 71 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और पेपर लीक में लाभान्वित हुए अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करती रहेगी। बहस के दौरान अदालत ने इस मामले की जांच सी.बी.आई. को सौंपने से इन्कार कर दिया।

बहस के दौरान ए.बी.वी.पी. की ओर से दायर जनहित याचिका में पैरवी कर रहे वकील आयुष मल ने कहा कि एस.ओ.जी. तो स्वयं ही राज्य सरकार के गृह विभाग के मातहत कार्य करती है, तो कैसे माना जा सकता कि वह सरकार द्वारा नियुक्त अफसरों के खिलाफ निष्पक्ष जांच करेगी।

- **याचिकाकर्ता का तर्क है कि, एस.ओ.जी. राज्य सरकार द्वारा गठित है, इसलिए उसकी निष्पक्षता पर प्रश्नचिन्ह लगता है। अदालत ने इस तर्क को स्वीकार नहीं किया।**
- **अतः न्यायालय ने यह भी कहा कि, वह एस.ओ.जी. की जांच की डे-टुडे मॉनिटरिंग नहीं करेगी, परन्तु अगर कोई नया तथ्य उजागर होता है, तो वह पुनः इस मामले को सुनेगी।**
- **इस मामले में रीट भर्ती-2021, लैवल-1 परीक्षा को खारिज करने से संबंधित याचिका पर अदालत 25 जुलाई को सुनवाई करेगी।**

उल्लेखनीय है कि ए.बी.वी.पी. की ओर से दायर याचिका में यह आरोप लगाया गया है कि इस पेपर लीक की साजिश में कई वरिष्ट अफसरों और नेताओं का हाथ है। बहस के दौरान अधिवक्ता आयुष मल ने अदालत को बताया कि डी.पी. जारोली ने मीडिया में बयान दिया है कि उसे राजनैतिक संरक्षण मिला हुआ है। उन्होंने अदालत को कहा है कि इस मामले में डी.पी. जारोली के बयान को जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष रिकॉर्ड नहीं किया गया था, जबकि वह एक मुख्य आरोपी है। उन्होंने कहा कि अदालत केवल डी.पी. जारोली द्वारा पुलिस के सामने दिये गये बयानों को ही रिकॉर्ड पर ले रही है। आयुष मल ने कहा कि एस.ओ.जी. ने इस जांच का मज़ाक बना कर रख दिया है और संतोषजनक जांच पड़ताल नहीं की है। उन्होंने कहा कि एस.ओ.जी. ने तो डी.पी. जारोली को क्लीन चिट दे दी है।

सुनवाई के दौरान एस.ओ.जी. के ए.डी.जी. अशोक राठौड़ ने अदालत को बताया कि इस मामले में 71 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है और 65 लोगों के खिलाफ आरोप पत्र भी पेश कर दिये गये हैं। उन्होंने कहा कि 11 लोगों ने हाई कोर्ट में अग्रिम जमानत की याचिका भी दायर की है और कई अन्य लोगों ने नियमित जमानत के लिए भी याचिका दायर की है।

उन्होंने अदालत को बताया कि, डी.पी. जारोली से पूछताछ की गई तो उसने बताया कि प्रदीप पाराशर को परीक्षा के दौरान जिला समन्वयक इसलिए नियुक्त किया गया था क्योंकि वर्ष 2011, 2012, 2015, 2019 में भी प्राइवेट पार्टी को ''डिस्ट्रिक्ट

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

द्रौपदी मुर्मू

जयपुर, 7 जुलाई (का.सं.)। राष्ट्रपति पद के लिए एनडीए की तरफ से उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को जयपुर दौरे पर रहेंगी। वे यहां क्लार्क्स आमेर होटल में भाजपा सांसदों और विधायकों से मुलाक़ात करेंगी और समर्थन की अपील करेंगी।

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने मुर्मू के आने की जानकारी एक परिपत्र के माध्यम से दी है। भाजपा के सभी सांसदों और विधायकों के लिए जारी इस परिपत्र में कटारिया ने जानकारी दी है, कि राष्ट्रपति पद की एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को जयपुर आएँगी। उनका सभी सांसद और विधायकों से व्यक्तिगत मिलने का कार्यक्रम है। इसी दिन सांसदों-विधायकों की संयुक्त बैठक भी रखी गई है।

- **एन.डी.ए. की राष्ट्रपति उम्मीदवार, द्रौपदी मुर्मू 12 जुलाई को क्लार्क्स आमेर होटल में भाजपा विधायकों, सांसदों से मिलेंगी।**

नैशनल हाई स्पीड रेल कॉर्पोरेशन के प्रबंध निदेशक बर्खास्त!

साल भर पहले ही केन्द्रीय सरकार ने कई अधिकारियों की वरिष्ठता लांघकर सतीश अग्निहोत्री को प्रबंध निदेशक नियुक्त किया

-श्रीनंद झा-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। शर्मसार करने वाले एक घटनाक्रम के तहत केन्द्र सरकार ने नैशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड (एन.एच.एस.आर.सी.एल.) के प्रबंध निदेशक सतीश अग्निहोत्रि को आज बर्खास्त कर दिया। अग्निहोत्रि को एक वर्ष पूर्व ही आउट ऑफ टर्न बेसिस पर एक स्पेशल केस के रूप में नियुक्त किया गया था।

- **हालांकि रेलवे बोर्ड ने स्पष्ट नहीं किया कि, अग्निहोत्री को क्यों पद मुक्त किया गया है, पर, अपुष्ट समाचारों के अनुसार, गत 2 जून को लोकपाल ने ऑर्डर पारित कर, सी.बी.आई. को अधिकृत किया था कि, अग्निहोत्री के खिलाफ जांच करें। आरोप है कि, रेलवे विकास निगम लिमिटेड के अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक के रूप में, अग्निहोत्री ने एक प्राइवेट कंपनी कृष्णा पटनम रेल कंपनी लिमिटेड को 11 सौ करोड़ रूपये की राशि गैर कानूनी तरीके से ''डाइवर्ट'' करी थी।**

एन.एच.एस.आर.सी.एल. के कम्पनी सचिव के नाम लिखे रेल्वे बोर्ड के 7 जुलाई के पत्र में कहा गया है कि ''सक्षम प्राधिकरण ने सतीश अग्निहोत्रि की सेवा समाप्ति को मंजूरी दे दी है। उन्हें तुरन्त प्रभाव से पद छोड़ने के निर्देश दिए गए हैं। पत्र में कहा गया है कि ''एन.एच.एस.आर.सी.एल. में वर्तमान में निदेश्क (परियोजना) का प्रभार संभाल रहे राजेन्द्र प्रसाद को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से तीन माह तक के लिए या आगामी आदेशों तक, इनमें से जो भी पहले हो, प्रबंध निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार संभालने को कहा गया है।''

गत वर्ष 10 जून को लिखे गए एक पत्र में उक्त पोस्ट के लिए निकाले गए विज्ञापन में वर्णित आयु और पात्रता शर्तों में छूट देते हुए रेलवे बोर्ड ने अग्निहोत्रि की नियुक्ति को आरंभ में तीन वर्ष के लिए मंजूर किया था।

हालांकि, रेलवे बोर्ड के पत्र में बर्खास्तगी आदेश के किसी कारण को स्पष्ट नहीं किया गया है, फिर भी अग्निहोत्रि की सेवा समाप्ति का कारण लोकपाल कोर्ट का 2 जून 2022 का

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

राजनाथ सिंह

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। संसद के मानसून के एक सप्ताह पहले, रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ''पार्लियामेन्ट्री कन्सल्टेव कमेटी ऑन डिफेंस'' के सदस्यों को हाल ही में लॉन्च की गई ''अग्निपथ'' योजना के विभिन्न पहलुओं के बारे में आवश्यक जानकारी देंगे। ज्ञातव्य अब आगे तीनों रक्षा सेवाओं में नई भर्ती अग्निपथ योजना के जरिये ही होगी।

- **रक्षा मंत्री, तीनों सेनाध्यक्ष व रक्षा मंत्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारी, रक्षा मंत्रालय की संसदीय समिति को अग्निपथ स्कीम के विभिन्न पहलुओं पर ''ब्रीफ'' करेंगे।**

रक्षामन्त्रालय की एक प्रैस-विज्ञप्ति में कहा गया है कि इस ब्रीकिंग में रक्षा सचिव, तीनों सैन्य प्रमुख तथा रक्षा मन्त्रालय के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

अमेरिका का वोटर, राजनीतिक नेतृत्व में परिवर्तन चाहता है

71 प्रतिशत वोटर चाहते हैं, राष्ट्रपति बाइडन अगला चुनाव न लड़ें, पर इसका मतलब यह भी नहीं की ट्रम्प चुनाव लड़े

-सुकुमार साह-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। एक नये सर्वेक्षण के अनुसार, अमेरिकावासियों की बहुत बड़ी संख्या 2024 में नया राजनैतिक नेतृत्व चाहती है।

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी-हैरिस पोल बताता है कि 71 प्रतिशत अमेरिकन नहीं चाहते कि दो साल बाद होने वाले राष्ट्रपति चुनाव में राष्ट्रपति बाइडन खड़े हों। केवल 29 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वर्तमान राष्ट्रपति को अगला चुनाव लड़ना चाहिये।

मतदाताओं से पूछा गया था कि वे क्यों चाहते हैं कि बाइडन 2024 का चुनाव न लड़ें। ऐसा कहने वाले लोगों, जिनका कहना है कि उन्हें अगला राष्ट्रपति चुनाव नहीं लड़ना चाहिये, में से 45 प्रतिशत लोगों का कहना है कि वे एक खराब राष्ट्रपति हैं, 30 प्रतिशत लोगों का कहना है कि उनकी उम्र बहुत हो गई है, तथा 25 प्रतिशत लोगों का विचार था कि परिवर्तन होना चाहिए।

सर्वे के आयोजक मार्क जेन ने कहा, ''डेमोक्रेटिक'' प्रेसीडेंशियल प्राइमरी में उन्हें केवल 30 प्रतिशत डेमोक्रेट्स के वोट ही मिल पायेंगे।

यह पोल बताता है कि बाइडन की अप्रूवल रेटिंग 40 प्रतिशत से भी नीचे पहुँच गई है क्योंकि मँहगाई तथा गैस की बढ़ती हुई कीमतें मेहनतकश अमेरिकनों को बहुत परेशान कर रही हैं।

28 तथा 29 जून को हुये इस पोल में, पूरे देश के 1,308 पंजीकृत मतदाता शामिल किये गये। किन्तु उल्लेखनीय बात यह है कि जनता की ओर से बाइडन के मामूली समर्थन का मतलब यह कदपि नहीं है कि 2024 में रिपब्लिकनों की जीत स्वतः ही हो जायेगी।

हार्वर्ड-हैरिस सर्वेक्षण में पाया गया कि जहाँ अमेरिकनों की बहुत बड़ी संख्या नहीं चाहती कि बाइडन अगला चुनाव लड़ें, वहीं बहुत से लोगों ने यही बात उस समय कहीं, जब पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के बारे में पूछा गया।

- **बाइडन को दोबारा राष्ट्रपति के रूप में नहीं देखना चाहने के, इन लोगों ने कई कारण बताये, उनमें प्रमुख है कि, बाइडन वृद्ध है; अच्छे राष्ट्रपति साबित नहीं हुए, तथा कुछ यह मानते हैं कि, अब बदलाव का समय आ गया है।**
- **बाइडन की भांति, ट्रम्प को भी दोबारा राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में नहीं देखना चाहते हैं, अधिकांश वोटर।**
- **पूर्व राष्ट्रपति ट्रम्प के खिलाफ नाराजगी का मुख्य कारण है, 6 जनवरी 2021 को, राष्ट्रपति का चुनाव हारने के बाद, ट्रम्प के उनके समर्थकों द्वारा कैपिटल हिल पर आक्रमण कर, कब्जा करने का प्रयास।**
- **हारवर्ड युनिवर्सिटी व हैरिस पोल द्वारा गत 28 व 29 जून को किये गये सर्वे में मतदाताओं का यह मूड उजागर हुआ था।**

60 प्रतिशत से अधिक मतदाताओं ने कहा कि ट्रम्प को 2024 में चुनाव नहीं लड़ना चाहिये तथा सिर्फ 39 प्रतिशत लोग चाहते थे कि वे फिर से चुनाव लड़ें। सर्वे में शामिल लोगों में से 36 प्रतिशत लोगों का कहना था कि ट्रम्प को नाइट हाउस पहुँचने के एक और प्रयास से परहेज़ करना चाहिये क्योंकि सनकी आदमी हैं, जबकि 33 लोगों ने कहा कि उनके राष्ट्रपति बनने से देश के टुकड़े हो जायेंगे।

30 प्रतिशत अन्य लोगों ने कहा कि वे अमेरिका की राजधानी में 6 जनवरी 2021 को हुये दंगे के कारण ट्रम्प की वापसी का विरोध कर रहे हैं।

यह पूछे जाने पर कि अगर 2024 के चुनाव में डोनाल्ड ट्रम्प तथा जो बाइडन ही खड़े होते हैं तो क्या आप किसी मध्यमार्गी या नरमपंथी उम्मीदवार पर विचार करेंगे अथवा नहीं, तो 60 प्रतिशत लोगों ने ''हाँ'' में उत्तर दिया। पोल में मतदाताओं से पूछा गया कि अगर राष्ट्रपति का 2024 में होने वाला चुनाव आज हो जाये तथा चुनाव डोनाल्ड ट्रम्प एवं जो बाइडन के बीच हो, तो आप किसे वोट देंगे। इस तुलना में, ट्रम्प को मामूली सी बढ़त मिली। 43 प्रतिशत लोग ट्रम्प के पक्ष में थे, जबकि बाइडन के पक्ष में 40 प्रतिशत लोग थे। 17 प्रतिशत लोग अनिश्चित रहे।

अगर 2024 के चुनाव आज हो जायें तथा मुकाबला डोनाल्ड ट्रम्प एवं कमला हैरिस के बीच हो तो पोल में सामने आया कि 45 प्रतिशत लोग ट्रम्प को पसंद करेंगे तथा 39 प्रतिशत लोग

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)

संयुक्त किसान मोर्चा

-जाल खंबाता-
-राष्ट्रदूत दिल्ली ब्यूरो-

नई दिल्ली, 7 जुलाई। कांग्रेस सांसद तथा प्रवक्ता दीपेन्द्र सिंह हूडा ने गुरूवार को मोदी सरकार पर आरोप लगाया कि सरकार पिछले रास्ते से किसान-विरोधी कृषि कानूनों को फिर से लाने की कोशिश कर रही हैं। उन्होंने कहा कि किसानों की वाजिब माँगों को पूरा करने से भाजपा सरकार द्वारा इनकार किये जाने के विरोध में, संयुक्त किसान मोर्चा (एस.के.एम.) ने राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शनों की श्रृंखला शुरू करने का निर्णय लिया है।

- **मोर्चा अगस्त माह में पुनः प्रदर्शन व धरना आरम्भ करेगा, क्योंकि ''सरकार ने जो वादे किये थे, पूरे नहीं किये हैं।**

हूडा ने कहा कि एस.के.एम. युवा-विरोधी तथा किसान-विरोधी अग्निपथ स्कीम तथा लखीमपुर खादी हत्याकांड

(शेष अंतिम पृष्ठ पर)